नागराज

बनाम

मैसूर राज्य

[के. सुब्बा राव रघुबर दयाल और जे. आर. मुधोलकर, जे. जे.]

अभियोजन के लिए मंजूरी-कर्तव्य के दौरान कथित अपराध के लिए पुलिस-परीक्षण के उप-निरीक्षक-जवाबी मामले में साक्ष्य, यदि माना जा सकता है-ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ मंजूरी आवश्यक है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम 5), एस. एस.127-132,197.-मैसूर पुलिस अधिनियम, 1908 (1908 का 5),-एसएस 4 (सी), 8,26 (1) और (3)।

अपीलकर्ता, मैसूर राज्य में पुलिस का एक उप-निरीक्षक, के. के. की शिकायत पर मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता और एक अन्य व्यक्ति ने टी को बुरी तरह पीटा था, और अपीलकर्ता, जब जबरन टी ले जा रहा था, और के द्वारा टी को माफ करने का अनुरोध किया गया था, तो उसने दो व्यक्तियों पर जानबूझकर गोली चला दी। अपीलार्थी का मामला, जिस पर उसका जवाबी मामला आधारित है, यह है कि जब वह और एक सिपाही, गिरफ्तार करने के बाद, टी को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, 20 या 30 व्यक्तियों ने उन पर हमला किया और टी को बचाया। कौवे ने उसे के आने तक इंतजार करने के लिए कहा। अपीलार्थी के इनकार करने पर भीड़ ने धमकी दी।तभी के आया।अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने पहले हवा में गोली चलाई, लेकिन जब लोगों ने पथराव किया और उसे पकड़ लिया, तो दो गोलियां चली, जिससे दो लोग घायल हो गए। उसकी रिवॉल्वर और दो मज़हर छीन लिए। टी के मामले में अपीलकर्ता द्वारा

तैयार किया गया, और लोगों ने उसे पीटा। इन व्यक्तियों को मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है। सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की प्रतिबद्धता को रद्द करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट एस. एस. के प्रावधानों को देखते हुए राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता था। 132 और 197 दंड प्रक्रिया संहिता।उच्च न्यायालय ने प्रतिबद्धता आदेश को रद्द करने के लिए सत्र न्यायाधीश के संदर्भ को खारिज कर दिया।विशेष अनुमति द्वारा अपील पर, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि (1) अपीलकर्ता को अकेले राज्य सरकार द्वारा खारिज किया जा सकता है और इसलिए, धाराओं के तहत मंजूरी दी जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 197 आवश्यक थी; (2) एक पुलिस अधिकारी पर उस अपराध के लिए मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसके बारे में पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के दौरान होने का आरोप लगाता है; (3) जब कोई मामला और जवाबी मामला दोनों सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने घटना के बारे में अपने कथन को प्रथमदृष्टया स्थापित कर लिया है और प्रति मामले में प्रत्यर्पण आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करना एस के तहत उस मंजूरी को धारण करने के लिए पर्याप्त है।132 दंड प्रक्रिया संहिता आवश्यक थी, और (4) पुलिस अधिकारी के लिए यह निर्णायक रूप से साबित करना आवश्यक नहीं है कि वह मंजूरी के अभाव की याचिका उठाने से पहले एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर कर रहा था।

अभिनिर्धारित किया कि (1) एस. एस. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। 4 (सी), 8 और उप-एस. एस.(1) & (3) एस.26 मैसूर पुलिस अधिनियम के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक उप-निरीक्षक को बर्खास्त कर सकता है और इसलिए, अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, भले ही उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए कथित अपराध किए हों।

(2) न्यायालय मंजूरी की आवश्यकता पर तभी विचार कर सकता है जब कार्यवाही में दर्ज साक्ष्य या मामले की परिस्थितियों से या तो निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित करना संभव हो कि कथित अपराध किया गया था या संभवतः एस. एस. 127 और कोड 128 के तहत कार्रवाई के संबंध में किया गया था। यदि कार्यवाही के किसी भी स्तर पर अदालत को यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी की कार्रवाई एस. एस. 127 और संहिता 128 में के प्रावधानों के भीतर आती है। न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि मंजूरी आवश्यक थी। शिकायत के साथ आगे बढ़ने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र शिकायत में लगाए गए आरोपों से उत्पन्न होता है न कि आरोपी द्वारा लगाए गए आरोप या दर्ज किए गए साक्ष्य के परिणामस्वरूप मामले में अंततः क्या स्थापित होता है।

मजाजोज डोबे बनाम एच. सी. भारी, [1955] 2 एस. सी. आर. 925, संदर्भित।

(3) वर्तमान मामले में अभिलेख से यह प्रतीत नहीं होता है कि साक्ष्य प्रथमदृष्टया अपीलार्थी के इस तर्क को स्थापित करता है कि सरकार की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस प्रश्न का निर्णय इस मामले में साक्ष्य के आधार पर किया जाना है न कि दूसरे मामले में प्राप्त साक्ष्य और निष्कर्षों के आधार पर।

(4) ताकि अपीलकर्ता एस के प्रावधानों का लाभ प्राप्त आदेश सके।132 संहिता के अनुसार, उसे यह स्थापित करना होगा कि (i) एक गैरकानूनी सभा थी जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी, (ii) सभा को तितर-बितर करने का आदेश दिया गया था, (iii) सभा आदेश पर तितर-बितर नहीं हुई थी या यदि कोई आदेश नहीं दिया गया था, तो उसके आचरण ने तितर-बितर नहीं होने का दृढ़ संकल्प दिखाया था; और (iv) उन परिस्थितियों में जब उसने ऐसी सभा के सदस्यों के खिलाफ बल प्रयोग किया था।यह उसे उसी तरीके से करना पड़ता है जैसे एक अभियुक्त को अपने बचाव में

एक अपवाद स्थापित करना होता है। इसलिए, वर्तमान मामले में अभियुक्त को अदालत को यह दिखाना होगा कि कथित अपराध उसके कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए थे और उसके ऐसा करने पर अदालत यह अभिनिर्धारित करेगी कि शिकायत धाराओं 132 कोड के तहत सरकार की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है।।

आगे अभिनिर्धारित किया कि यदि न्यायालय निर्णय देता है कि एस 132 संहिता उस मामले में लागू होती है जिसमें मंजूरी के बिना शुरू की गई शिकायत पर कार्यवाही अमान्य होगी और इसके पारित होने के लिए उचित आदेश यह होगा कि कार्यवाही को हटा दिया जाए और शिकायत को खारिज कर दिया जाए।

आपराधिक अपीलीय न्यायनिर्णयःदाण्डिक अपीलीय सं 172/ 1962

मैसूर उच्च न्यायालय के आपराधिक पुनरीक्षण मामले संख्या 100/1961 के निर्णय और आदेश दिनांक 7 मार्च, 1962 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

आर. गोपालकृष्णन, अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से बी. आर. एल. अयंगर और पी. डी. मेनन।

न्यायालय का निर्णय 8 मई 1963 को रघुबर दयाल जे. द्वारा दिया गया था।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील मैसूर उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है जिसमें सत्र न्यायाधीश, शिमोगा डिवीजन द्वारा दिए गए संदर्भ को खारिज कर दिया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को एस. एस. के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए सत्रों को सौंपने के प्रतिबद्धता आदेश को रद्द करने की सिफारिश की गई है। 307 और 326, आई. पी. सी., इस आधार पर कि मजिस्ट्रेट एस. एस. 132 और दंड प्रक्रिया संहिता की 197 के प्रावधानों को देखते हुए राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता था।

अपीलकर्ता के खिलाफ मामला एक केंचप्पा की शिकायत पर शुरू किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि उप-निरीक्षक और एक अन्य व्यक्ति ने थिम्मा को बुरी तरह पीटा था और उप-निरीक्षक ने थिम्मा को जबरन ले जाते समय और केंचप्पा द्वारा अनुरोध किया था कि अगर उसने दुर्व्यवहार किया है तो थिम्मा को माफ कर दें, तो हनुमानथप्पा और शिवलिंगप्पा पर अपनी रिवॉल्वर से जानबूझकर गोली चला दी। इस शिकायत पर, प्रारंभिक जांच के बाद, मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता नागराज को मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

घटना के तथ्यों के अनुसार, घटना के तथ्य, अपीलकर्ता और काउंटर मामले के आधार के अनुसार, ये हैं। अपीलकर्ता मैसूर राज्य में पुलिस का उप-निरीक्षक था। सितंबर 1959 में उन्हें कडूर तालुक के यागती में तैनात किया गया था। 7 सितंबर, 1959 को उन्होंने अवैध शराब बनाने वाले गिद्दा को गिरफ्तार किया और उसे सिपाही के साथ पुलिस स्टेशन भेज दिया।इसके बाद, उसने थिम्मा को गिरफ्तार कर लिया, जो शराब बनाने में गीदा के साथ मिली हुई थी। जब थिम्मा को सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल द्वारा पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तो लगभग 20 या 30 लोगों की भीड़ उन पर दौड़ पड़ी, उन्हें घेर लिया और पुलिस अधिकारियों ने उन पर हमला किया और थिम्मा को बचा लिया। नागराज ने उन लोगों से हिंसा का सहारा नहीं लेने, बल्कि शांत रहने के लिए कहा।लोगों ने-हालाँकि, सलाह पर ध्यान नहीं दिया, सिपाही को पकड़ लिया और नागराज को तब तक वहाँ रहने के लिए कहा जब तक कि एक केंचप्पा न आ जाए।इस पर, उप-निरीक्षक ने उन्हें फिर से बिना कोई परेशानी पैदा किए जाने के लिए कहा और कहा कि उनके पास केंचप्पा का इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। लोगों ने उसे और सिपाही को धमकी दी कि अगर वे वहाँ से चले गए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।तभी केंचप्पा आया और फिर इन लोगों ने सब-इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर को घेर लिया, उनकी और कॉन्स्टेबल की जान को खतरा

होने की आशंका में, पहले अपनी रिवॉल्वर से हवा में गोली चलाई और जब लोगों ने उन पर पथराव किया और उनसे भिड़ गए, तो रिवॉल्वर से दो गोलियां चली गईं और दो व्यक्तियों, हनुमंतप्पा और शिवलिंगप्पा को घायल कर दिया।कैंचप्पा ने रिवॉल्वर, गोला-बारूद की थैली के साथ चमड़े का थैला और निषेधाज्ञा मामले के संबंध में उपनिरीक्षक द्वारा तैयार किए गए दो मजार छीन लिए।लोगों ने उप-निरीक्षक को पीटा और यह कहते हुए उसे एक तालाब में ले गए कि वे उसे उसमें फेंक देंगे।हालाँकि, उन्हें एक बसप्पा के विरोध पर रिहा कर दिया गया था।

जिन व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस दिन नागराज पर हमला किया था, उन्हें धारा 147,332,341 और 395 के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि एस. एस.143, 147, 149, 224, 225, 395 और 34, आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की प्रतिबद्धता को रद्द करने के लिए संदर्भ दिया क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मामले एक घटना से उत्पन्न हुए कि उप-निरीक्षक उस समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उसे बलपूर्वक एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करना पड़ा क्योंकि उसका अपना और अपने अधीनस्थ का जीवन खतरे में था और इसलिए एस के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी थी। एस. 197 सरकार में निहित पुलिस के उप-निरीक्षक को बर्खास्त करने की शक्ति के रूप में उनके खिलाफ अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के लिए संहिता की आवश्यकता थी। उनकी यह भी राय थी कि भले ही उप-निरीक्षक ने बिना किसी औचित्य के बर्खास्त कर दिया हो, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, एस 132 के तहत मंजूरी।संहिता आवश्यक थी। उन्होंने कहाः

"अब, यह नहीं कहा जा सकता है कि उस समय वह स्पष्ट रूप से ड्यूटी पर था और थिम्मा को सब-इंस्पेक्टर के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में पुलिस स्टेशन ले जा रहा था।इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उसे घेर लिया और थिम्मा को बचा लिया।इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक गैरकानूनी सभा थी जिसे उप-निरीक्षक बलपूर्वक तितर-बितर करने का हकदार था। अब एस 132 सी. आर. पी. सी. स्पष्ट रूप से सी. आर. पी. सी. के अध्याय IX के तहत कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों के अभियोजन के लिए एक बाधा है। जो स्थानीय सरकार की मंजूरी के बिना गैरकानूनी सभाओं से संबंधित है।''

उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि सत्र न्यायाधीश अपीलकर्ता के इस कथन को व्यावहारिक रूप से स्वीकार करने में गलत था कि वह कई व्यक्तियों से घिरा हुआ था जिन्होंने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और उन्होंने थिम्मा को बचाया और इसलिए वह गैरकानूनी सभा को बलपूर्वक तितर-बितर करने का हकदार था।

उच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस के उप-निरीक्षक को पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा सेवा से हटाया जा सकता है और इसलिए धाराओं 197 के तहत मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं उठ खड़ा हुआ। इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के समक्ष यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा सरकार की मंजूरी के बिना मामले का संज्ञान लिया गया था। 132, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि एक गैरकानूनी सभा थी और यह कि पुलिस अधिकारी संहिता की धारा 128 से 131 में से किसी के तहत सभा को तितर-बितर करने का इरादा रखता था। उच्च न्यायालय ने बाद में कहाः

"धारा 132 सी. आर. पी. सी. का किसी भी अपराध के घटकों से कोई लेना-देना नहीं है।यह अभियोजन के खिलाफ एक संरक्षण है।इसका लाभ प्राप्त आदेशने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को यह साबित आदेशने की आवश्यकता नहीं है कि शिकायत किए गए कार्य दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 132 में उल्लिखित परिस्थितियों में किए गए थे। पी. सी. दूसरे शब्दों में, उसे न्यायाधीश के सामने ऐसी सामग्री और परिस्थितियों को रखना चाहिए जो इस निष्आदेश को उचित ठहराती हों कि एक गैरकानूनी सभा हुई थी और जिन कार्यों की शिकायत की गई थी, वे उस सभा को तितर-बितर आदेशते समय किए गए थे।''

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मामले में स्थापित तथ्यों पर निर्णय लेना सत्र न्यायाधीश का काम है। सीआर पी. सी. 132 लागू था और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले के तथ्य इसे एस के प्रावधानों के भीतर लाते हैं। सीआर पी. सी. 132 सत्र न्यायाधीश को यह मानते हुए शिकायत को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता थी कि यह धाराओं सी आर पी. सी. 132 के तहत वर्जित था।

अंत में, उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि पहले दूसरे पक्ष के खिलाफ सत्र मामले की सुनवाई की जाए और यदि इसकी सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश संतुष्ट हो कि अभियुक्त के खिलाफ शिकायत एस 132 सीआर पी. सी., के तहत वर्जित थी। उसके लिए यह उचित होगा कि वह केवल उसी आधार पर उस शिकायत को अस्वीकार कर दे।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय में चार तर्क उठाए हैंः(1) पुलिस के उपनिरीक्षक के रूप में अपीलकर्ता को अकेले राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है और इसलिए, धाराओं 197 के तहत मंजूरी दी जा सकती है। अपने

कर्तव्य के निर्वहन में किए गए अपराधों के उनके अभियोजन के लिए संहिता की धारा आवश्यक थी। (2) कि एक पुलिस अधिकारी पर राज्य सरकार की मंजूरी के बिना एक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जो पुलिस अधिकारी का आरोप है कि चेप्टर IX के कोड (3)तहत कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान हुआ था। जब एक मामला और एक जवाबी मामला दोनों को सत्र न्यायालय में परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, तो यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने घटना के बारे में अपने कथन को प्रथमदृष्टया स्थापित किया है और प्रति मामले में प्रतिबद्ध आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करना एस 132, सीआर. पी. सी. के तहत उस मंजूरी को धारण करने के लिए पर्याप्त है। (4) कि पुलिस अधिकारी के लिए यह निर्णायक रूप से साबित करना आवश्यक नहीं है कि वह एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर कर रहा था, इससे पहले कि वह अभियोजन पक्ष से प्रतिबंध के रूप में मंजूरी के अभाव की याचिका उठा सके।

हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अपीलकर्ता, उपनिरीक्षक को अकेले राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। मैसूर पुलिस अधिनियम, 1908 की खंड 4 (सी)। 1908 का 5), जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है, यह प्रावधान करता है कि जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय न हो, अधिनियम में "निरीक्षक" शब्द, ऐसे नियमों और आदेशों के अधीन, जो सरकार पारित कर सकती है, में 'उप-निरीक्षक' शामिल है।' खंड 8 में कहा गया है कि ऐसे ग्रेडों के निरीक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करे और सभी ग्रेडों के निरीक्षकों की बर्खास्तगी सरकार में निहित होगी। यह इन दो प्रावधानों के आधार पर है कि अपीलकर्ता के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सरकार है जो उसे बर्खास्त कर सकती है क्योंकि वह, हालांकि एक उप-निरीक्षक है, एस 8 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निरीक्षक है। विवाद ठीक नहीं है । यह सभी श्रेणियों के निरीक्षकों की बर्खास्तगी है जो सरकार में निहित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न श्रेणियों के

निरीक्षक हैं। कुछ श्रेणियों के निरीक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन सभी श्रेणियों के निरीक्षकों की बर्खास्तगी सरकार में निहित है। इस संदर्भ में एस 8 में 'इंस्पेक्टर' शब्द है। उप-निरीक्षक को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वह संभवतः किसी भी श्रेणी का निरीक्षक नहीं हो सकता था। एस 26 की उप-धारा (1) अधिनियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि उप-अधिकारियों द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी। (3) उस ओर से सहायक अधीक्षक और उप-ग्रेड से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया जा सकता है। (3) एस 8 के प्रावधानों के अधीन वह प्रदान करता है। महानिरीक्षक के पास सहायक अधीक्षक के दर्जे से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को दंडित करने का अधिकार होगा। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक एक उप-निरीक्षक को बर्खास्त कर सकता है जो सहायक अधीक्षक के ग्रेड से नीचे का पुलिस अधिकारी है। इसलिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, भले ही उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए कथित अपराध किया हो।

उठाए गए अन्य विवादों से निपटने से पहले हम चेप्टर IX के प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का जिसका शीर्षक 'गैरकानूनी सभाएँ' है।' खंड 127 किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसी भी गैरकानूनी सभा या पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की किसी भी सभा को सार्वजनिक शांति में खलल डालने, तितर-बितर करने का आदेश देने का अधिकार देती है और आगे यह प्रावधान करती है कि ऐसी सभा के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे आदेश पर तितर-बितर हों। यदि ऐसी सभा के सदस्यों द्वारा ऐसी आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है,धारा 128 मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सभा को तितर-बितर करने के लिए नागरिक बल का उपयोग करने के लिए अधिकृत करती है। इस तरह की आज्ञा दिए बिना भी नागरिक बल का उपयोग किया जा सकता है, अगर सभा का

संचालन तितर-बितर नहीं होने का दृढ़ संकल्प दिखाता है। ऐसा अधिकारी किसी भी पुरुष व्यक्ति को सभा को तितर-बितर करने में सहायता करने के लिए बुला सकता है और सभा का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार और सीमित भी कर सकता है। धारा 129 और 130 ऐसी सभा को तितर-बितर करने में सैन्य बल के उपयोग और ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए बुलाए गए सशस्त्र बलों की कमान संभालने वाले अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है।खंड 131 सशस्त्र बलों के किसी भी कमीशन अधिकारी को, किसी भी मजिस्ट्रेट के साथ किसी भी संचार की अनुपस्थिति में में, कुछ परिस्थितियों में सशस्त्र बलों की मदद से ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए अधिकृत करती है। अधिकारी और व्यक्ति जो तितर-बितर करने के उद्देश्य से इन प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं, गैरकानूनी सभा को एस के प्रावधानों के तहत अभियोजन से संरक्षित किया जाता है। 132 जिस पर अपीलकर्ता निर्भर करता है।इस अपील के प्रयोजन के लिए इस खंड के सुसंगत भाग में कहा गया हैः

> "इस अध्याय के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोजन किसी भी मामले में शुरू नहीं किया जाएगा।दंड न्यायालय, राज्य सरकार की मंजूरी के अलावा; और
>
> (क) इस अध्याय के तहत सद्भावना से कार्य करने वाला कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी,
>
> x x x x
>
> यह समझा जाएगा कि उसने इस प्रकार अपराध किया है।''

यह स्पष्ट है कि जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अदालत में शिकायत की जाती है और यह संकेत देते हुए आरोप लगाया जाता है कि पुलिस अधिकारी ने एस. एस127 और संहिता की धारा 128 के तहत कार्य किया था या

कथित रूप से कार्य किया था। और ऐसा करने में कुछ अपराध की शिकायत की गई है, न्यायालय तब तक शिकायत पर विचार नहीं करेगा जब तक कि यह प्रतीत नहीं होता है कि राज्य सरकार ने उस पुलिस अधिकारी के अभियोजन को मंजूरी दे दी थी।यदि शिकायत में आरोप ऐसे तथ्यों का संकेत नहीं देते हैं, तो अदालत के पास सरकार की मंजूरी लेने और शिकायत पर विचार करने से इनकार करने के लिए ऐसी मंजूरी की अनुपस्थिति में में कोई आधार नहीं हो सकता है।उसे शिकायत के साथ उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए जैसे उसने किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायतों के संबंध में किया होगा।

अदालत के लिए इस बात पर विचार करने का अवसर होगा कि क्या शिकायत सरकार की मंजूरी के बिना दायर की जा सकती है, जब कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में अदालत को यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी की कार्रवाई एस. एस. 127 और 128 अधिनियम के प्रावधानों के भीतर आती है। यह या तो तब हो सकता है जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और ऐसा सुझाव देता है या जब साक्ष्य या परिस्थितियाँ इसे प्रथमदृष्टया दर्शाती हैं। तथापि, अभियुक्त का केवल सुझाव न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि मंजूरी आवश्यक थी। न्यायालय मंजूरी की आवश्यकता पर तभी विचार कर सकता है जब निम्न में दर्ज साक्ष्य सेःकार्यवाही या मामले की परिस्थितियों में या तो निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित करना संभव है कि कथित आपराधिक आचरण किया गया था या संभवतः एस. एस. 127 और कोड के 128 के तहत कार्रवाई के संबंध में किया गया था।

अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया जाता है कि यदि मंजूरी के प्रश्न का निर्णय पहली बार में ही नहीं किया जाता है जब कोई शिकायत दायर की जाती है या जब आरोप लगाया जाता है कि उन पर सरकार की मंजूरी के बिना कथित अपराधों के लिए

मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 132 संहिता के अनुसार, इस खंड द्वारा दिया गया संरक्षण निरर्थक होगा क्योंकि यह संरक्षण देने का उद्देश्य यह है कि पुलिस अधिकारी को किसी भी तुच्छ शिकायत से परेशान नहीं किया जाए। अभियुक्त का कुछ ऐसा उत्पीड़न हो सकता है, लेकिन न्यायालय के पास उन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित करने का कोई साधन नहीं है जिनमें आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त का अभियोजन ऐसी कार्रवाई के संबंध में था क्योंकि शिकायत में आवश्यक परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया गया था जो इस तथ्य का संकेत देते हैं और अभियुक्त के नंगे शब्द को अन्यथा अभिनिर्धारित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह एक शिकायतकर्ता उन तथ्यों का उल्लेख करना छोड़ सकता है जिनके लिए आरोपी पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी, उसी तरह आरोपी के भी ऐसे आरोप लगाने की संभावना है जिससे मंजूरी के अभाव में शिकायत खारिज हो सकती है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि शिकायत के साथ आगे बढ़ने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र शिकायत में लगाए गए आरोपों से उत्पन्न होता है न कि आरोपी द्वारा लगाए गए आरोप या दर्ज किए गए साक्ष्य के परिणामस्वरूप मामले में अंततः क्या स्थापित होता है।

इस संबंध में अभियोजन के संबंध में इस न्यायालय की टिप्पणियों को उचित रूप से संदर्भित किया जा सकता है, जिसके लिए एस 197 संहिता के प्रावधान लागू होते है। माताजोग डोबे बनाम एच. सी. भारी (1) में, इस प्रश्न के संबंध में "क्या शिकायत दर्ज होते ही और उसमें निहित आरोपों पर मंजूरी पर विचार करने की आवश्यकता है?", कहा गया थाः

> "यह प्रश्न कार्यवाही के किसी भी चरण में उत्पन्न हो सकता है। शिकायत में यह खुलासा नहीं किया जा सकता है कि अपराध का गठन करने वाला कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया

था या किया जाना था; लेकिन बाद में पुलिस या न्यायिक जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के दौरान भी सामने आने वाले तथ्य मंजूरी की आवश्यकता को स्थापित कर सकते हैं। मंजूरी आवश्यक है या नहीं, यह चरण-दर-चरण निर्धारित करना पड़ सकता है। आवश्यकता मामले की प्रगति के क्रम में खुद को प्रकट कर सकती है।''

अतः यह तर्क कि एक पुलिस अधिकारी पर राज्य सरकार की मंजूरी के बिना एक ऐसे अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसके बारे में वह आरोप लगाता है कि यह चेप्टर IX संहिता का स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनका मात्र आरोप इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा और अदालत को उस शिकायत को खारिज करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसका उसने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर उचित रूप से संज्ञान लिया था।

तीसरा तर्क वास्तव में यह है कि न्यायालय उस मंजूरी को आवश्यक मान सकता है यदि अपीलकर्ता प्रथमदृष्टया यह दिखा सके कि उसकी कार्रवाई, जिसकी शिकायत की गई है, एस. एस.127 और कोड के 128 के तहत अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के संबंध में थी। यह मानते हुए कि यह कानूनी स्थिति है, यह उस अभिलेख से प्रतीत नहीं होता है जिसमें सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के आदेश शामिल हैं कि इस मामले में साक्ष्य प्रथमदृष्टया यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी का तर्क कि उसके कार्यों की शिकायत की गई थी, ऐसा था जिसके लिए सरकार की मंजूरी के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से कहा है कि सत्र न्यायाधीश इस तरह के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे और उन्होंने केवल आरोपी के बयान की स्वीकृति पर संदर्भ दिया था, जिसके लिए कोई औचित्य नहीं था।अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया जाता है कि केवल यह तथ्य कि गैरकानूनी

सभा का हिस्सा होने का आरोप लगाने वाले कुछ व्यक्तियों पर राज्य द्वारा मुकदमा चलाया गया था और मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को भी सौंपा गया था, प्रथमदृष्टया यह स्थापित करता है कि अभियुक्त का एस 132 कोड से के तहत मंजूरी की आवश्यकता के बारे में तर्क सही है। अन्य अभियुक्त की प्रतिबद्धता उस मामले में साक्ष्य के आधार पर है और इस मामले में उठाए गए प्रश्न का निर्णय करने के लिए कानूनी रूप से विचार नहीं किया जा सकता है। सवाल का फैसला इस मामले में साक्ष्य के आधार पर किया जाना है न कि दूसरे मामले में साक्ष्य और निष्कर्षों के आधार पर। इसलिए, तीसरे विवाद का कोई बल नहीं है।

अगला प्रश्न और तब तय आदेशने के लिए वास्तविक प्रश्न यह निर्धारित आदेशना है कि अभियुक्त को एस 132 मामले में कोड के प्रावधानों का लाभ प्राप्त आदेशने के लिए क्या दिखाना है। इस तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए और इस सवाल पर एक स्पष्ट निर्णय को टालने के लिए कि क्या उसका आचरण एक अपराध है या नहीं, अपीलकर्ता को यह दिखाना होगा कि (i) एक गैरकानूनी सभा थी या पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा थी जिससे सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी होने की संभावना थी; (ii) ऐसी सभा को तितर-बितर करने का आदेश दिया गया था; (iii) या तो सभा इस तरह के आदेश पर तितर-बितर नहीं हुई थी या, यदि कोई आदेश नहीं दिया गया था; उसके आचरण ने तितर-बितर नहीं होने का दृढ़ संकल्प दिखाया था; और (iv) कि परिस्थितियों में उसने ऐसी सभा के सदस्यों के खिलाफ बल का उपयोग किया था।उसे इन तथ्यों को ठीक उसी तरह स्थापित करना होगा जैसे एक अभियुक्त को किसी आपराधिक मामले में अपने आचरण के बचाव में किसी अन्य अपवाद को स्थापित करना होता है। यह पर्याप्त रूप से तय है कि अभियोजन पक्ष को अपराध को इस अर्थ में साबित करना है कि अपराध उन परिस्थितियों में किया गया था जिनमें कोई अपवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता था और इसलिए, यदि अभियुक्त ऐसी परिस्थितियाँ

स्थापित करता है जो या तो निर्णायक रूप से न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्थापित करती हैं या न्यायालय को यह विश्वास दिलाती हैं कि मामला उस अपवाद के भीतर आता है जो यह साबित करने के लिए अभियुक्त की ओर से पर्याप्त अनुपालन होगा कि अपवाद साबित करने के संबंध में उसकी जिम्मेदारी क्या थी।अतः वर्तमान मामले में अभियुक्त को न्यायालय को यह दिखाना होगा कि कथित अपराध ऊपर वर्णित परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए थे।उनके इस तरह के प्रदर्शन पर, यह अभिनिर्धारित करना न्यायालय का कर्तव्य होगा कि एस 132 कोड के तहत सरकार की मंजूरी के बिना शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता था। यह दिखाना अभियुक्त द्वारा उन तथ्यों को स्थापित करने के बराबर नहीं है जो उसके लिए एस 79 के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होंगे। भारतीय दंड संहिता के बारे में जैसा कि हमें उद्धृत कुछ मामलों में सोचा गया था। खंड 79 भारतीय दंड संहिता उन परिस्थितियों से संबंधित है जो साबित होने पर शिकायत किए गए कार्यों को अपराध नहीं बनाती हैं। एस 132, सीआर. पी.सी की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित की जाने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं जो शिकायत किए गए कार्यों को कोई अपराध नहीं बनाती हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराधों के संबंध में शिकायत का संज्ञान लेने में सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यदि एस 132 के संरक्षण की मांग के लिए परिस्थितियाँ स्थापित की जानी हैं। संहिता के अनुसार कथित आचरण को कोई अपराध नहीं बनाना था, राज्य सरकार की मंजूरी से अभियोजन का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। जिन मामलों में हमें संदर्भित किया गया था, उनमें इस भेद पर विचार नहीं किया गया था। उन मामलों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है जो अंततः इस आधार पर तय किए गए थे कि शिकायत में या तो आरोप या रिकॉर्ड पर साक्ष्य से जो सामने आया था, उसके साथ मिलकर इस निष्कर्ष को उचित ठहराया गया था कि शिकायत की गई कार्रवाई एस. एस. 127 और

संहिता की धारा 128 के तहत आई थी। यह कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना न्यायालय में ऐसी कार्रवाई के संबंध में कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है।

विचार करने के लिए अंतिम प्रश्न यह है कि यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता था, तो उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, अर्थात, क्या न्यायालय को अभियुक्त को आरोपमुक्त करना चाहिए या उसे आरोप से बरी करना चाहिए यदि उसके खिलाफ आरोप बनाया गया है या केवल कार्यवाही को छोड़ देना चाहिए और संहिता के तहत अभियोजन के मामले में विचार के अनुसार आरोपमुक्त या दोषमुक्ति का कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब सत्र न्यायाधीश संतुष्ट हो कि तथ्य साबित हुए हैं तो मामले को एस 127 और संहिता की धारा 128 की शिकायत के दायरे में लाया जाता है। 127 और संहिता की धारा 128 संहिता के अनुसार तब वह यह मानते हुए शिकायत को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है कि यह उस खंड द्वारा वर्जित है। हम इसे उन परिस्थितियों में पारित किया जाने वाला सही आदेश मानते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय को अभियुक्त को दोषमुक्त करने या बरी करने का औपचारिक आदेश पारित करना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।यदि एस 132 लागू होता है, शिकायत सरकार की मंजूरी के बिना शुरू नहीं की जा सकती थी और इस तरह से शुरू की गई शिकायत पर कार्यवाही अमान्य होगी, न्यायालय को उन कार्यवाही को करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब कार्यवाही अमान्य हो जाती है, तो न्यायालय इस आदेश के अलावा कोई आदेश पारित करने में सक्षम नहीं होता है कि कार्यवाही को हटा दिया जाए और शिकायत को खारिज कर दिया जाए।

हम तदनुसार उच्च न्यायालय के आदेश को सही मानते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।